सत्यमेव जयते

**असंशोधित**

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2022

टर्न-13/मधुप/03.03.2022

( अन्तराल के बाद )

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2021-22 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा । इसके लिए दिनांक- 03 एवं 04 मार्च, 2022 की तिथि निर्धारित है। वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्या संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | - 75 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | - 73 मिनट |
| जनता दल (यूनाइटेड) | - 45 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | - 19 मिनट |
| सी0पी0आई0(एम0एल0) | - 12 मिनट |
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | - 5 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | - 4 मिनट |
| विकासशील इंसान पार्टी | - 3 मिनट |
| सी0पी0आई0(एम0) | - 2 मिनट |
| सी0पी0आई0 | - 2 मिनट |

इंडियन नेशनल कांग्रेस से माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह । 19 मिनट ।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद ।

महोदय, बजट की जो यह प्रस्तावना पेश की गई है, निश्चित रूप से सरकार द्वारा 6 सूत्रों की बात की गई है और पहला ही सूत्र है स्वास्थ्य । मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा हमलोगों को यह बताया गया कि 11.80 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवाया जा चुका है और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में या अन्य संबंधित चिकित्सकीय संस्थानों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की व्यवस्था करायी जा रही है । निश्चित रूप से हम बड़े-बड़े अस्पतालों के भवनों का भी निर्माण कर रहे हैं लेकिन एक समस्या जो हमलोगों को आज भी महसूस होती है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की जो संख्या चाहिये होती हैं, कहीं न कहीं उसमें भारी अंतर है । छोटे से छोटे जो जिला अस्पताल हैं, हमारे यहाँ का ही औरंगाबाद का एक उदाहरण ले लीजिये, 52 चिकित्सकों की आवश्यकता है । मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 सालों में कभी भी वे सारे पद भरे नहीं गये हैं । कहीं न कहीं चिकित्सकों का घोर अभाव रहता है । हम बहुत बढ़िया भवन बना लें, बहुत सारे लैब इस्टेबलिश करवा लें, संयत्र लगवा लें लेकिन अगर चिकित्सक नहीं होंगे तो कौन उनकी देखभाल करेंगे और कौन आम लोगों की जो चिकित्सा है, व्यवस्था है उसको हैंडल करेंगे । तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह चिकित्सकों की है और कर्मियों की है । तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी वृहद फोकस होना चाहिए । औरंगाबाद की जहाँ तक बात है, चिकित्सा महाविद्यालय की बात हमलोग वर्षों से करते आ रहे हैं और यह जो जिला है मैं समझता हूँ कि एन0एच0 पर अवस्थित है और आये-दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और नजदीकी जो महाविद्यालय हैं चिकित्सा के, वे या तो फिर आपको गया जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको बनारस जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको पटना जाना पड़ेगा । तो निश्चित रूप से एक चिकित्सा महाविद्यालय की औरंगाबाद को भी आवश्यकता है । मैं आपलोगों के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से आपलोगों से यह आग्रह करता हूँ कि चिकित्सा महाविद्यालय की वहाँ भी स्थापना हो । महोदय, भवन निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होगा, डॉक्टरों के पदस्थापन से, व्यवस्था में कड़ाई से यह होगा । अभी कुछ दिनों पहले हमलोग बैठे हुये थे, बात हो रही थी, सिविल सर्जन वहाँ उपस्थित थे, मैं समझता हूँ कि इतनी सारी महिला चिकित्सकों

के बावजूद भी महिलाओं का ऑपरेशन जो होता है, गायनी का ऑपरेशन जो होता है वह सरकारी अस्पतालों में नहीं संभव हो पाता है । तो कहीं न कहीं व्यवस्था में भी ढिलाई है और उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार या तो वहाँ के सिविल सर्जन होते हैं और नहीं तो वहाँ के सदर अस्पताल के जो अधीक्षक होते हैं, वे होते हैं । तो व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हो रही है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । निश्चित रूप से राज्य सरकार ने कोरोना में बहुत उपलब्धि हासिल की है, ऑक्सीजन का कहीं भी हमलोगों के क्षेत्र से तो ऑक्सीजन कैमूर तक, भभुआ तक, जहानाबाद तक, गया तक गया है । लेकिन यह भी एक विषय है कि हर जगह जब यह ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लग जायेंगे तो उस ऑक्सीजन जेनरेशन का आखिर हम करेंगे क्या ? हम इतने ऑक्सीजन जो जेनरेट करेंगे, उसका हम करेंगे क्या ? क्या उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है कि उसको हम कैसे खपत करेंगे ? क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है, यह परिस्थिति तो उस समय जेनरेट हुई जब कोरोना पीक पर था और हमलोगों को यह मालूम नहीं था कि यह फिर आयेगा, वृहत रूप से आयेगा या उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यह हमलोगों को पता नहीं है लेकिन अभी तो जो थर्ड वेव का जो हमलोगों को लग रहा है, इंटेंसिटी कम है । तो वह जो ऑक्सीजन का जेनरेशन होगा तो उसका हमलोग कहाँ यूज करेंगे, इसपर भी फोकस होना चाहिए ।

महोदय, दूसरा सूत्र है शिक्षा । मैं समझता हूँ कि इसमें एक अच्छी पहल है कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में भवन निर्माण हेतु इसमें व्यवस्था की गई है 7530 करोड़ की स्वीकृति दी गई है । निश्चित रूप से सराहनीय कदम है लेकिन फिर वही दिक्कत, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की उपलब्धता होनी चाहिए उसी प्रकार से, अगर हम केवल भवन बनाने के लिए करें तो कहीं न कहीं वह बेमानी लगती है, जब शिक्षकों का ही पदस्थापन न हो, शिक्षकों की समुचित संख्या न हो और प्राथमिक विद्यालय का तो आलम यह है कि छोटे-छोटे बच्चों को, मैं समझता हूँ कि दो-दो कि0मी0, तीन-तीन कि0मी0, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन हैं तो उनके बच्चों को दूर जाना पड़ता है, दूसरे गाँवों में जाना पड़ता है, कहीं-कहीं तो सड़क पार करके जाना पड़ता है, वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ खतरा रहता है । तो एक तरफ हम प्राथमिक विद्यालयों के ही भवन का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों की । जब प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा ही ठीक से ग्रहण नहीं करेगा तो आगे की शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है ? टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल निश्चित रूप से होना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए, इन सब विषयों

पर, हमलोग बहुत सारे स्मार्ट क्लासेज लगाये गये हैं, मैं समझता हूँ कि कई स्मार्ट क्लासेज के उद्घाटन में भी हमलोग गये हैं लेकिन आज की परिस्थिति देखियेगा तो मालूम चलेगा कि कहीं चोरी हो गई स्मार्ट क्लास के सामानों की, कहीं बैट्री नहीं है तो कहीं कुछ हो गया । उसकी भी व्यवस्था हमलोगों को पूर्ण करवानी पड़ेगी और कोरोना के इस काल में टेक्नॉलोजी की जो सम्भावनाएँ बढ़ी हैं, ऑनलाईन क्लासेज का प्रचलन बढ़ा है तो उस टेक्नॉलोजी के माध्यम से हमलोग शिक्षा की व्यवस्था और वृहद पैमाने पर मैं कह रहा हूँ, कोशिश तो की गई है लेकिन उसको और वृहद पैमाने पर ले जाने की आवश्यकता है । इसलिये उस ओर भी सरकार का ख्याल जाना चाहिए । जहाँ तक बजट की बात है, मैं समझता हूँ कि टेक्नॉलोजी पर भी इस बजट से खर्च होनी चाहिए ।

तीसरा सूत्र उद्योग से संबंधित है, महोदय । निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार फोकस तो कर रही है लेकिन उसका फलाफल अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है । सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ पर है कि राज्य सरकार के पास अपना कोई लैंड बैंक नहीं है जिसपर उद्योग-धंधे स्थापित किये जा सकें । तो उसपर राज्य सरकार का फोकस होना चाहिए, जो भी उद्यमी हैं, जो उद्योग-धंधे लगाना चाहते हों, उनको रियायती दर पर जमीन मुहैया करायें उद्यमियों को या वैसे इंडस्ट्रीयलिस्ट को जो बिहार आना चाहते हैं, पहले तो वे आना नहीं चाहते हैं और अगर आना भी चाहते हैं तो भ्रष्टाचार और यह जमीन की अनुलब्धता के कारण बोरिया-बिस्तर समेट कर वापस चले जाते हैं । तो यह सबसे बड़ा जो विषय है वह जमीन का है ।

..क्रमशः..

टर्न-14/आजाद/03.03.2022

..... क्रमशः .....

श्री आनन्द शंकर सिंह : भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से इसमें इतना ज्यादा है कि जो लोग उद्योग-धंधा यहां पर स्थापित करने के लिए आते हैं, घुमकर के पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण लौटकर चले जाते हैं तो कहीं न कहीं यह सबसे बड़ा जो लैकूना है इस विभाग और उद्योंग-धंधे स्थापित करने में, उसमें सबसे बड़ा जो लैकूना है, वह जमीन का हमारे यहां है । जमीन का लैंड बैंक उपलब्ध कराइए और उद्यमियों को उचित दर पर जमीन उपलब्ध कराइए । इसमें जो डाटा दिया गया है महोदय, मैं समझता हूँ कि 15986 नये उद्यमियों के द्वारा 800 करोड़ रू0 निवेश किया गया है । दूसरा डाटा यह है कि 4000 महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया, 4000 अत्यंत पिछड़ी जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया और उसके

बाद दिया गया है 3999 अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया है। जो डाटा 4000 और 3999 के बीच में ही रह जा रहा है महोदय, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं यह खानापूरी की गई है और 4000-4000 यह एकुरेट डाटा चाहे महिला उद्यमियों की बात हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति के उद्यमियों की बात हो, चाहे एस0सी0/एस0टी0 उद्यमियों की बात हो । 3999 से 4000 यह तो महोदय लग रहा है जैसे लिख दिया गया है, इसमें कहीं न कहीं पदाधिकारियों की उदासीनता दिखती है । चौथा जो सूत्र है महोदय, इसमें आया है कि कृषि से संबंधित क्षेत्रों का निश्चित रूप से इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मेंशन किया गया है कि अतिरिक्त रोजगार के लिए किसी भी उत्पाद को अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की व्यवस्था की बात की गई है इस बजट में । मैं तो समझता हूँ कि कृषकों को अपने ही क्षेत्र में अगर उनका उत्पादन बिक जाय तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन हम अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन बेचने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह कहीं से भी मैं समझता हूँ कि उचित प्रतीत नहीं होता है । आज जो किसान अपना धान उत्पादन कर रहा है, वह भी उससे उचित दर पर एम0एस0पी0 पर नहीं लिया जा रहा है । पैक्स के जो सहकारी समितियां हैं, उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो सरकार के द्वारा रेट तय की जाती है उससे 400-500रू0 प्रति क्विंटल कम दिया जाता है, उसपर सरकार नहीं चेत रही है तो किसानों को यह ख्वाब दिखा रही है कि आपका जो उत्पाद है, हम उसको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचवाने का काम करेंगे, यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है । खाद की समस्या से हम सभी लोग अवगत हुए हैं । जिस प्रकार से खाद की किल्लत हुई है और मैं देख रहा था, सुन रहा था सुबह में ही एक प्रश्न आया था और माननीय मंत्री जी का जो बयान आया था कि सब जगह खाद उपलब्ध करा दिया गया था । मैं खुद औरंगाबाद जिला से आता हूँ और वहां पर खाद के लिए इतनी मारा-मारी और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा किसानों को लाठियों और डंडों से मारा जा रहा है । जब खाद उपलब्ध था तो फिर आप किसानों को लाठी और डंडों से मार रहे हैं । कहीं-कहीं तो ऐसा भी देखा गया कि कोई किसान 20 बोरा खाद दूसरे राज्य से लेकर आया है तो उसपर छापा मारा जा रहा है । वह किसी तरीके से दूसरे राज्य से खाद लेकर उपलब्ध कराया है तो उसपर भी छापामारी चल रही है तो कहीं न कहीं आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में माल बेचवाने की बात करते हैं और किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पाते, उनका जो फसल होता है, धान होता है, गेहूं होता है, उसको भी बेचने की व्यवस्था आपकी नहीं है । उसको भी

एम0एस0पी0 नहीं मिलता है तो आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं बेईमानी है ।

जिस प्रकार से तीन काले कानून आये, मैं समझता हूँ कि किसानों के द्वारा अगर इतना लम्बा-चौड़ा विरोध नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों कानून वापस नहीं होते । कल तक हमारे मित्रगण उसी काले कानून के बारे में प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे लेकिन आज जब वापस हो गया तो उनके बारे में जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते । मैं समझता हूँ कि यह सरकार कितनी किसानों के प्रति सजग है वो इनकी मनोदशा का बयान करती है ।

हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था की बात करते हैं, किसान तब न खेती करेगा जब सिंचाई की व्यवस्था होगी । हरियाही परियोजना हो या उत्तर कोयल परियोजना हो, सभी परियोजनायें लंबित थी और 2015 के चुनाव में जब मोदी जी गया आये थे मगध की धरती पर तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप लोगों के खेतों में लाल पानी नहीं पहुँचा दूँगा, तब तक मैं दोबारा आपलोगों से वोट मांगने नहीं आऊंगा । दोबारा अब क्या सर 2020 का भी चुनाव पार कर गया, 2019 का भी चुनाव पार कर गया और दोबारा भी आये लेकिन आज तक किसानों के खेतों में लाल पानी नहीं आया तो उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । इन मुद्दों को आज अन्तर्राज्यीय मुद्दा बनाकर इतनी ढ़िलाई बरती जा रही है, उन पदाधिकारियों पर भी दोषारोपण होना चाहिए आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार द्वारा राशि मुहैया कराने के बाद भी उदासीनता बरकरार है । आज तक औरंगाबाद हो या गया हो या जहानाबाद हो ....

(व्यवधान)

भाई साहेब, उस समय डबल ईंजन की सरकार थी और झारखंड में भी आपकी सरकार थी और उसके बावजूद भी लाल पानी औरंगाबाद के किसानों को, जहानाबाद के किसानों को या गया के किसानों को नहीं मिल पाया । आप खेतों में सिंचाई की बात करते हैं तो कहां से होगा, जब आपकी परियोजनायें पूर्ण नहीं होगी...

(व्यवधान)

देखिए मुँह मत खोलवाइए, निश्चित रूप से आपका एन0डी0ए0 का गठबंधन बड़ा मजबूत है । लेकिन कल हमारे मित्र बोल रहे थे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि गठबंधन तो जोरदार है लेकिन गठबंधन के भी कुछ नियम होते हैं । गठबंधन के नियमों पर मैं समझता हूँ कि आपलोग सफल नहीं हैं । सरकार के मंत्री कुछ और बोलते हैं, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं और दोनों का एक-दूसरे के बातों से इतेफाक नहीं होता । यह कहीं न

कहीं कमी है । एक ईंजन आगे खिंच रहा है और दूसरा ईंजन पीछे खिंच रहा हैं। इसलिए कहीं न कहीं आपलोग एक-दूसरे पर इतेफाक नहीं रख रहे हैं तो आपलोग इतेफाक रखिए । गठबंधन का मतलब विचारों का भी गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री जी के विचारों से और जदयू के विचारों से इतेफाक रखिए, आपलोग इतेफाक नहीं रखना चाह रहे हैं । जिस प्रकार से यह सारी बातें हो रही है ।

महोदय, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है (व्यवधान)

भाई, गठबंधन समस्याओं पर एकमत होने पर गठबंधन होता है, कार्यक्रमों, नीतियों और विचारों का गठबंधन होता है .......

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : आपलोगों का न तो नीति मिल रहा है, न विचार मिल रहा है और न समस्या एक है, सब कोई एक-दूसरे को, स्थिति यही है । यह गठबंधन आपके परिस्थितियों का गठबंधन है, आपलोग भी समझते होंगे । इसलिए समझिए इन चीजों को ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने 19 मिनट में दो माननीय सदस्यों का नाम दिया था।

अध्यक्ष : एक ही आदमी का नाम आया, इनको समय 19 मिनट दिया गया, अब आप बैठ जाइए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : धन्यवाद सर, लेकिन एक बात सुन लीजिए महंगाई पर -

सखी सैईया तो बहुते कमायेत हय,
महंगाई डाईन खाय जायत हय ।
इसके चलते सभी लोग त्रस्त हैं ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया है ।

आज माना कि इतना आसान नहीं
इस सपने को हकीकत हो जाना,
लेकिन जिद है कुछ पाने की,
तो इतना कठिन भी नहीं है,
सपने को हकीकत में बदल जाना ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट का पूरा आकार का समग्र बजट पेश किया गया है, इसमें चौतरफा विकास का चिंतन हुआ है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ग्रामीण

विकास को विशेष ध्यान दिया गया है । बिहार के लगभग 2,37,651.19 करोड़ रू0 का वर्तमान बजट से स्पष्ट है कि किस प्रकार यह बजट सरकार के सामाजिक क्षेत्र और ढाँचागत विकास को अपना आवंटित केन्द्र किया है । इस बार के बजट में सामाजिक सेवा पर 40.20 प्रतिशत, आर्थिक सेवा पर 25.25 प्रतिशत और सामान्य सेवा पर 27.82 प्रतिशत का आवंटन रखा गया है । यह बजट दर्शाता है कि सरकार का बजट का बड़ा हिस्सा है । अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्तर्गत महिलाओ, प्रक्रिया युवाओं सबका चिंतन मनन हुआ है । आज आपका ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहेंगे

...... क्रमशः .....

टर्न-15/शंभु/03.03.22

श्री संजीव चौरसिया : ..क्रमशः.. कि इस बजट के आकार में कोरोना के कार्यकाल में भी वृद्धि, जहां संपूर्ण देश में अलग-अलग प्रकार से डगमगाती हुई दिखायी दे रही थी, आर्थिक वृद्धि दर्ज की गयी है 2.5 प्रतिशत का विकास दर हमने हासिल किया है । शिक्षा के क्षेत्र में जिन छः बिन्दुओं पर माननीय महोदय कह रहे थे अगर देखने का चश्मा विकासात्मक दृष्टिकोण से रखेंगे तो विकास ही विकास नजर आयेगा । इन छः बिन्दुओं पर अलग-अलग प्रकार से अगर शिक्षा में हम देखते हैं तो लगभग 16.50 प्रतिशत की वृद्धि पूरी मजबूती के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किया गया है । जब हमलोग विद्यार्थी परिषद् में थे तो सरकार से उस समय मांग करते थे कि बजट का छः प्रतिशत हो, लेकिन आज बजट का 16.50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार के तरफ से दिया गया है । जो अपने आप में शिक्षा जगत का बढ़ता हुआ कदम है । इसके अन्तर्गत 39 हजार 191 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । यानी कि शिक्षा पर 3.44 प्रतिशत की वृद्धि पिछली बार हुई है । लगभग 6298 प्लस टू स्कूलों के भवन के लिए 7530 करोड़ रूपये की मंजूरी की गयी है । 6421 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के पूर्व और पश्चात् जब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो 1886 में स्थापित जो इंजीनियरिंग था उसकी भी संख्या आप देखेंगे तो नगण्य प्रकार से थी । 2004 में एन0आइ0टी0 का गठन और आजादी के पश्चात् अलग-अलग प्रकार से जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है । आज आप शिक्षा के आकार को देखेंगे डिजिटल के माध्यम से हो चाहे शिक्षा के पूरे भारत के मापदंड के हो तो हमने विश्वविद्यालय का निर्माण करने का भी काम किया है और शिक्षा के अनेक बिन्दुओं को छूने का काम किया है । वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए अगर हमलोगों ने टीकाकरण

के दृष्टि से लगभग 11.80 करोड़ अलग-अलग प्रकार से फस्ट डोज और सेकेंड डोज देने का काम किया है । यह अपने आप में देश का अभूतपूर्व उदाहरण है । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के दृष्टि से 16134.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है । यानी कि इसके आकार को भी बढ़ाकर जो कि 22.2 प्रतिशत अधिक है । हम जानते हैं कि कोरोना के वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से विश्व को पूरी तरह से प्रभावित किया है और 2020 से कोरोना की महामारी से हम प्रभावित हैं, पर हमलोगों ने अलग-अलग प्रकार से जो आक्सीजन प्लांट अलग-अलग देशों में होता था और हमलोगों ने बिहार के दृष्टि से आक्सीजन प्लांट के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था करने का जो सराहनीय काम किया है और लगभग 122 जगहों पर पी0एच0सी0 आक्सीजन जेनरेशन प्लांट चालू किया है और समय-समय पर उसका उपयोग अपने आप में दृढ़ीकरण इस बात को साबित करता है । यह स्वाभाविक है कि इसके लिए मेनटेनेन्स की जरूरत पड़ेगी, सरकार अपने चिंतन से इसके मेनटेनेन्स की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी । महोदय, पांच नये मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई है इस बात का द्योतक है कि सरकार चिंतित है कि प्रत्येक कमिश्नरी से लेकर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे हो उसके मनन के साथ-साथ क्रियाशील भी करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़ावा मिला है । अब तक उद्योगों के क्षेत्र में सरकार की जब चिंता होती थी तो लगता था कि दूसरे प्रांत में ही उद्योग लग पायेगा, पर बिहार का दृष्टिकोण, बिहार के विकास की किरण अब बढ़ने लगी है तो उद्योग के लिए भी निवेशक बिहार आना प्रारंभ किये हैं । इथेनॉल का प्रस्ताव जो बड़ा पूरे देश के अंदर दिखायी दे रहा है, बड़ी क्रांति की जो रचना है तो बिहार में 151 प्रस्ताव आये हैं जिसमें 17 प्रस्ताव केन्द्र को भी भेजने का काम किया है । इसके अन्तर्गत 35 करोड़ 80 लाख लीटर एकरारनामा भी हुआ है और पूरे कृषि के क्षेत्र में इससे बढ़ावा मिलेगा । इसका परिणाम यह है कि उद्योग को बढ़ावा के साथ-साथ इसके रफ्तार के लिए 1643.74 करोड़ का प्रावधान जो किया गया है । इस इथेनॉल के माध्यम से 2.60 नौकरियों का इजाफा भी निश्चित तौर पर होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरी का प्रावधान भी इस इन्डस्ट्रीज के माध्यम से होनेवाला है । जैसा कि उद्योग एक बड़ा केन्द्र बिन्दु बिहार की ओर आकर्षित होते जा रहा है । इसमें डबल इंजन सरकार का ही लाभ है कि केन्द्र और राज्य मिलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं । कृषि के क्षेत्र में जब देखेंगे कृषि के खाद्य संस्करण और कृषि निर्यात नीति से खेती किसानों की हालत सुधरेगी । इस क्षेत्र के विकास के रफ्तार के लिए 7712.30 करोड़ का

प्रावधान है । राज्य सरकार के द्वारा कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप जो जारी किया है उससे अनेक प्रकार के लाभ चूंकि विगत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी और हमने 2020-21 में कृषि विकास दर को 3.7 प्रतिशत जो था वह राज्य के किसान समर्थक नीतियों एवं हमारे किसान भाईयों के अथक परिश्रम का प्रतिफल है । महोदय, आपलोगों के संज्ञान में होगा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत प्रोत्साहित तालाबों के रख-रखाव हेतु 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठन को प्रदान किया गया था । इस प्रकार से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । महोदय, इन्फास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गांवो के विकास की ओर फोकस किया गया है । शहर के विकास तो हुए ही हैं, लेकिन ग्रामीण को विश्वस्तरीय सुविधा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19739.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है । गांव में रहनेवाले लोगों को सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य समेत अनेक तरह की सुविधा देने के लिए बजट में जो ध्यान रखा गया है यह उल्लेखनीय कदम है । महोदय, कल्याण के दृष्टि से सबसे बड़ा उत्थान की जहां आवश्यकता है पिछड़ा, अति पिछड़ा सामाजिक उत्थान के लिए, एस0सी0/एस0टी0 सबके लिए सबके साथ और वंचितों के विकास के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए इस सरकार ने 12375.7 करोड़ रूपये की मंजूरी की है । एस0सी0/एस0टी0 पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, बच्चों के अलावा दिव्यांग एवं वृद्धों के लिए भी बड़ी योजना में सकारात्मक पहल किया गया है और अलग-अलग प्रकार से छात्रावासों के निर्माण के लिए भी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अलग-अलग प्रकार से जो हुए हैं उसका बड़ा लाभ पूरे प्रकार से मिलने का हो रहा है । महोदय, सात निश्चय के तहत सरकार ने पार्ट-टू एक बड़ा हिस्सा लेकर जो बढ़ने का कदम हुआ है जो पिछली बार से इस बार भी 5 हजार करोड़ का जो आवंटन हुआ है सबसे बड़ा बल अलग-अलग प्रकार से देने का काम हुआ है । युवा शक्ति बिहार की प्रगति- बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड युवाओं को रोजगार ढूढ़ने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद व कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को 2025 तक चलाया जायेगा, चूंकि स्किल के माध्यम से युवा को हुनर बिहार के युवाओं को हुनर देने का काम करेंगे तो बिहार कहीं भी जाकर अपने हुनर को रोजगार के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है । यह बिहार का युवा है बिहार का नौजवान है । महोदय, युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाये गये हैं कुल 1153 करोड़ रूपये उपलब्ध है, आर्थिक युवाओं का बल । बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम

से स्वीकृत ऋण 4500 करोड़ के लगभग 1 लाख 17 हजार 923 कार्ड निर्गत हुए हैं और अब 700 करोड़ ऋण देने का प्रावधान करेंगे । कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 225 करोड़ का प्रावधान युवा शक्ति बिहार की प्रगति को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे । सशक्त महिला सक्षम महिला- यह बिहार सरकार की संकल्पना है कि पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक पहलुओं पर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो सभी चेतना को जागृत करते हुए जो आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस सरकार ने किया है यह अपने आप में उल्लेखपूर्ण है । महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना इसमें उनके द्वारा लगाये जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा । सक्षम महिला उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आधी आबादी को प्रोत्साहन के लिए कुल 900 करोड़ रूपये का प्रावधान है । महोदय, हर खेत को पानी अब प्लॉट का भी सर्वे कराया जा रहा है कि सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन हो । इस योजना में नदियों को आपस में जोड़ने का भी काम हो रहा है जो सबसे बड़ा सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी उस योजना का साकारमुख संरचना माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है, करने का काम बिहार के अंदर हो रहा है । भविष्य में हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जायेगा । सरकार प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध इसमें 600 करोड़ रूपये किये जायेंगे । सर्वे पूरा हो चुका है, बिहार को समझन है तो नदियों को समझना जरूरी होगा इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इसे समझने की आवश्यकता को आगे बढ़ाने का काम किया है । स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव- सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी, इसकी नियमित निगरानी होगी । गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन चूंकि प्रबंधन के जो सबसे बड़ा कचरा का प्रबंधन का काम जो गांवों में करने की योजना सरकार ने तय किया है उसको हम कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम करेंगे । प्रत्येक घर से ठोस कचरा लिया जायेगा तथा नालों के अंत में निकाले हुए गंदे जल का ट्रीटमेंट भी कराया जायेगा । सरकार का ध्यान गांवों पर है इस मद में 847 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे, शहरों की तरह कचरा प्रबंधन होना है, सोलर लाइट लगना है । स्वच्छ शहर विकसित शहर- सभी शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से किये जायेंगे । ..क्रमशः..

टर्न- 16/पुलकित/03.03.2022

(क्रमशः)

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण के लिए सात निश्चय की तरफ बढ़ा है । शहरी गरीबों के लिए पर्याप्त भवन बनाये, सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह और सबसे बड़ी रचना जो सरकार की योजना में है उससे कनेक्टिीविटी और आसान होगी । आसपास के गांव जोड़ते हुए मुख्य पथ और प्रखंड थाना, अनुमंडल, बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं नेशनल हाईवे सम्पर्कता के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जायेगा । शहरी इलाकों में भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिकता के आधार पर बनाने का काम हमलोगों ने किया है । प्रत्येक आठ से दस पंचायतों में पशु अस्पताल की व्यवस्था की जायेगी । लोगों द्वारा कॉल सेंटर में फोन करके और मोबाईल ऐप के माध्यम से सुविधाएं भी प्राप्त होंगी । टेली मेडिसिन के माध्यम से भी अलग-अलग प्रकार से इसके निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ी संकल्पना जो बिहार में थी कि छह घंटे से हमलोगों ने संकल्पना पूरी की है अब तो और चार घंटे के अंदर भी, चार से पांच घंटे के अंदर आने का काम अलग-अलग प्रकार से जोड़ने का होगा । जे0पी0 सेतु के बारे में आपको पता होगा, दो लेन के विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वीर कुंवर सिंह सेतु को भी चार लेन, मुंगेर रेल-सह-सड़क सेतु को दो लेन तथा सात नये पुलों के निर्माण प्रगति पर हैं जिनका निकट भविष्य में पूर्ण होनी की संभावना है । बिहार का यह बजट समग्र बजट है इसके लिए हमलोग जो मानकर चले हैं वह सबसे बड़ा कदम है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे । शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने का वाला जो राज्य को आगे बढ़ने का काम कर रहा है उसमें हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ी सुविधा के रूप में इस सरकार ने काम करने का काम किया है उन सब विषयों पर जब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को पाते हैं कि एक अलग-अलग प्रकार से राज्य ने विकास का जो पैमाना चलाया है जो आत्मबल शक्ति, गौरवमय इतिहास रचने का काम किया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान राज्य की सरकार ने किया है । आज राज्य की सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के लिए, म्यूजियम के उत्थान के लिए इस सबसे बड़े विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है । राज्य की सरकार में शहरीकरण के लिए, विकास के लिए अधिकतम दलों की रचना जो होती थी पूरे देश में यह दिखाई देता था कि शहरीकरण का क्षेत्र बिहार में कम बढ़ रहा है । आज बिहार सरकार ने शहरीकरण के दौर को आगे बढ़ाने का काम किया है । गांव भी बढ़ रहे हैं और शहर की

आबादी, गांव की आबादी को भी शहरीकरण के लाभ मिलने का काम हो । पटना के शहरों में भी मेट्रो की व्यवस्था से लेकर सड़कों के फोर लेन से लेकर अलग-अलग प्रकार से जो पटना रचता है, बसता है, आत्मा है बिहार की उस पटना को जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण के माध्यम से सरकार ने बजट का प्रावधान करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है वह धन्यवाद के पात्र है । आज गंगा परियोजना के माध्यम से, गंगा के क्लीन के माध्यम से डॉल्फिन जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं । वहां की डॉल्फिन जिस प्रकार से दिखाई देती है एक नेशनल हैरिटेज के रूप में डॉल्फिन वहां दिखाई देती है । इस रचना को सरकार ने योजना के तहत उसको ग्रीन डॉल्फिन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया है । सरकार की यही संकल्पना है उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, आज सब विषय पर सांस्कृतिक विरासत के विषय पर, आर्थिक विरासत के विषय पर और उच्च शिक्षा के विषय पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार ने की है आज अभिनन्दन के पात्र इस बजट के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और तो और जब हम कृषि के विकास की ओर देखेंगे क्योंकि बिना किसान के बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से मुफ्त बिजली से लेकर, फीडर से लेकर अनेक योजनाओं को किया है, यह मन का भाव है । इस आस्था की जब व्यवस्था का काम सरकार ने किया है उसके लिए अभिनन्दन है पर आस्था की व्यवस्था में कुव्यवस्था की चिंता और चिंतन नहीं हो सकती है उस आस्था में व्यवस्था की ही चिंतन हो सकती है। हमको इसके बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए । मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि -

‘‘तूफानों में भी जलता रहे वह दीया बनो,
बरसात में सैलाब न लाये वह दरिया बनो,
क्योंकि सहनशीलता से विकास होता है,
और उग्रवादिता से विनाश होता है ।’’

इसलिए सहनशील बनें और विकास के अग्रम कदम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करे तभी विकास का पैमाना इस पूरे राज्य में दिखाई देगा, क्योंकि बढ़ता बिहार, चढ़ता बिहार, गौरवमय बिहार, बिहार के युवाओं और जो उत्थान पूरे विश्व में कर रहा है । धन्यवाद है सरकार को बिहार के बिहारीपन बढ़ाने का काम किये हैं कि अनेक प्रांतों में बिहार का बिहारीपन जाता है वह कहीं न कहीं व्यंजन के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से, कला के माध्यम से, मधुबनी पेंटिंग से लेकर, भागलपुर पेंटिंग से लेकर सभी प्रकार के वह अपनी स्मृति छोड़कर

आने का काम करता है । इस स्मृति में बिहार का बिहारीपन लगातार झलकते रहता है, दिखते रहता है । आज अफसरशाही से लेकर, जो भी देखे बिहार का कीर्तिमान चारों ओर फैला हुआ है । आपने समय देने का काम किया है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई है । बिहार की अच्छाइयों की ओर देखना सीखें । जब अच्छाई नहीं दिखाई देगी, केवल चश्मे की बुराई ही बुराई दिखाई देगी तब विकास का पैमाना नहीं देख सकते हैं । इसलिए बड़ा लेंस अच्छाइयों का करें और बाई-फोकस करके देखें तो विकास की नजदीकियां, दूरियां दोनों दिखाने का काम करेगा । तब माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग दोनों प्लानिंग हमने करके आगे बढ़ाने का काम किया है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्ताव लाया गया है, उसको देखने के बाद अदम गोंडवी की दो पंक्ति याद आती है -

''कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी हैं ।''

जो फर्जीवाड़ा बजट प्रस्ताव में है, उसके कुछ बिन्दुओं की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । बजट में सरकार को केन्द्र से जो मिलने वाले टैक्स में शेयर है उसको 91,181 करोड़ रुपये दिखाया है, लेकिन कुछ दिनों पहले जब यूनियन का बजट आया, केन्द्र सरकार का जो बजट आया था उसमें केन्द्र सरकार ने बिहार को जो टैक्स वाला हिस्सा देने की बात कही वह सिर्फ 82,139 करोड़ का है । यानी 10 प्रतिशत का फर्जीवाड़ा टैक्स को बढ़ाकर के दिखाने के लिए आमद को बढ़ाकर दिखाने के लिए सरकार ने किया । इसी प्रकार से बिहार सरकार जो अपना टैक्स वसूलती है उसमें 18 प्रतिशत का इजाफा दिखाया गया है, लक्ष्य के रूप में । जो किसी भी अर्थशास्त्री से बात की जाय तो यह संभव नहीं है । वर्तमान स्थिति में यह बिहार में संभव नहीं है । सवाल यह उठता है कि यह बार-बार टैक्स को बढ़ाकर के दिखाने का, आंकड़ों से खेलने का सरकार का जो रवैया है इसका असल में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, वह बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है । पिछली बार सरकार ने शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति के ऊपर जो बजट एलोकेट किया था, सदन के अंदर, वह 39,351 करोड़ रुपये था लेकिन जो वास्तविक एलॉटमेंट हुआ वह 31 प्रतिशत कम हुआ क्योंकि आपने बजट के समय दिखाया कि हमारे पास खूब पैसा आ रहा है

और जब बजट एलोकेट करना था शिक्षा डिपार्टमेंट को तो आपने सिर्फ 27,347 करोड़ ही एलॉट किया । इसी तरह से एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सरकार ने जो बजट की घोषणा सदन के अंदर की उसमें 76 परसेंट की कटौती करते हुए बजट एलोकेट किया गया और ऐसे तमाम आंकड़े यहां पर हैं जो सरकार के लिफाफेबाजी का और बजट में जो दिखावटीपन किया गया है वह हमारे सामने है । महोदय, रुरल डेवलेपमेंट के ऊपर पिछली बार सरकार ने बजट एलॉटमेंट से जो वास्तविक बजट दिया था उसमें वह 40 प्रतिशत कम रहा । इसी तरीके से एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिवीटिज में 52 प्रतिशत की कटौती हुई तो इस तरह से हम आंकड़ों पर नहीं जाते बल्कि जो ज्वलंत सवाल बिहार के हैं और जो बजट से और सरकार की मंशा से जो चीजें गायब दिख रही हैं उसकी तरफ हम सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं । वह निश्चित तौर से रोजगार का मसला है । जो हाल में एन0एस0ओ0 का आंकड़ा है नेशनल स्टेस्टिसटिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है, वह यह कह रहा है कि 15 साल से लेकर के 59 साल की आयु में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेश्यो है वह बिहार में सिर्फ 27.5 प्रतिशत है । सिर्फ इतने लोगों का ही लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन एस0जी0डी0पी0 बजट में हो रहा है । इसका सीधा मतलब है कि बड़े हिस्से के पास कोई रोजगार नहीं है यह राष्ट्रीय आंकड़ा 41 प्रतिशत के आसपास है । रोजगार की बात करते हुए मुझे हाईकोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था, मैं उसको कोट यहां पर करना कहा था । माननीय हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में एक बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बे-दिमाग अर्थात् माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार । अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है, जितनी की बिहार की सरकार । ये हाईकोर्ट ने क्यों कहा ? शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक मसले पर रिट पिटीशन के जवाब में यह हाईकोर्ट ने कहा था और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-17/अभिनीत/03.03.2022

-क्रमशः-

श्री संदीप सौरभ : एस0टी0ई0टी0 की बहाली 2019 की बात अगर करें तो इसमें सरकार की तरफ से 37 हजार बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गयी हैं ।

पहली बार 12 मार्च को जो रिजल्ट आया कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाय, सबकी नौकरी पक्की समझी जाय । माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आलाधिकारियों ने प्रेस-कांफ्रेंस करके यह बात कही । अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एस0टी0ई0टी0 की विज्ञप्ति थी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार-बार बयान बदले जा रहे हैं । महोदय, मुझे दो-तीन बातें और कह लेने दी जाय ।

अध्यक्ष : आपको छः मिनट का ही समय दिया गया है ।

श्री संदीप सौरभ : बी0एस0एस0सी0 इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति को न मानते हुए 2014 के पहले का एम0सी0एल0 मांगा जा रहा है । अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति की जाय और उनका काम सिर्फ वही करें । इसके बावजूद सरकार उनका काम शिक्षकों से ले रही है । सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ का मामला है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में आंदोलन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे और आजतक उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी बहाली रूकी हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठ जाइये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, बस तीन संटेंस । महोदय, मैं सिर्फ तीन वाक्त बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा । मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली की विज्ञप्ति में विज्ञप्ति के अंदर यह नियम बनाया जाय कि विज्ञापन कब पूरा होगा, उसकी समय-सीमा का उल्लेख हो, एक बात ये । दूसरी बात, जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बहालियों का संकट है उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार की क्या होगी इसके ऊपर एक शेध पत्र सरकार जारी करे कि वह कबतक उसको शार्टआउट करेगी । तीसरा मामला है महोदय, युवाओं का संकट जो बिहार में दिख रहा है सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है, इसको लेकर सरकार क्या सोचती है ? इसे लेकर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त सदन, विधान सभा का एक अतिरिक्त सत्र जिसमें रोजगार और तमाम जो 22 तरह की बहालियां बिहार में पेंडिंग पड़ी हुई हैं विभाग और सरकार के मनमानेपन के चलते उसको लेकर एक अतिरिक्त सत्र हो । यही मैं सरकार से कहना चाहता हूं । आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सुश्री श्रेयसी सिंह ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट 2022-23 पर अपने विचारों को सदन पटल पर रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आसन के माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूं ।

एक समाज के रूप में कोरोना महामारी के कारण जिन परिस्थितियों को हमने झेला है उसका मर्म महान शायर जॉन एलियो की दो पंक्तियों से बयान करना चाहती हूं ।

''कौन सीखा है सिर्फ बातों से,
सबको एक हादसा जरूरी है ।''

अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने हम सबके जीवन में बड़े बदलाव ला दिए हैं । हम सबने अपनों को खोया है । बिहार में करोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है । यहां पचास हजार रुपये की दर से अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है जिसे केंद्र सरकार के आपदा राहत मद ने अनुमान्य किया है । बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में मृत व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है । राज्य में मुफ्त कोविड टेस्ट भी किये जा रहे हैं । स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में विगत दो साल से काफी सुधार हुआ है । बिहार में 11.280 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है । सौ से ज्यादा जगहों पर ऑक्सिजन प्लांट को शुरू कराया गया है । करोना महामारी से लड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी है और हम मजबूत हैं । यह हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के सौष्ठव को प्रकट करता है । इसके अलावा भारत सरकार ने बिहार को अपेक्षित सहायता प्रदान की है । राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा में भी बढ़ोत्तरी की है । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर था । विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा । बिहार सरकार ने 2.37 लाख करोड़ का बजट पेश किया है । इस बार बजट में आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार सृजन और कोविड के कारण पिछले दो वर्ष में स्थिर रहे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है । इस बजट में पूर्व से चली आ रही सात निश्चय-1 की योजनाओं को पूर्ण करने के साथ तथा सात निश्चय-2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिए राशि की भी व्यवस्था की गयी है । इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और वर्गों का विकास

संभव होगा । सामाजिक विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है यह इस बात से समझा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65 फीसदी खर्च होगा । अध्यक्ष महोदय, गौर करने वाली बात है कि 2004-05 का बजट मात्र 23 हजार 885 करोड़ का था लेकिन इस बार बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने यह बजट बढ़ाकर 2 लाख 37 हजारा 691.19 करोड़ रुपया का किया है । मतलब पिछले 16 वर्षों में बजट ने दस गुणा बढ़ोत्तरी किया है । जाहिर है कि बजट की राशि बढ़ेगी तो बिहार के विकास के कार्यों में भी इसकी झलक दिखायी देगी और 90 के दशक से आज के बिहार को नजदीक से देखने वाले ये लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके खेतों की सिंचाई । इसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर घर, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है । इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहले चरण का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है । युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत प्रथम फेज में राज्य के सात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया गया है । बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और साथ-साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी कानून बनाया गया है । स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी चालू है । अध्यक्ष महोदय, युवा शक्ति को बल देते हुए वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजनांतर्गत अबतक कुल 657 करोड़ की राशि वितरित की गयी है । वर्ष 2022-23 में इस योजनांतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है । यही नहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कुल 1496 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं । अभी तक इस योजना पर 702 करोड़ व्यय हुआ है और वर्ष 2022-23 में इस योजनांतर्गत 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तब राज्य में हरित आवरण का क्षेत्र मात्र नौ फीसदी रह गया था जबकि आज हरित आवरण का क्षेत्र बढ़कर 15 फीसदी के करीब पहुंच गया है । बिहार सरकार इतनी इको फ्रेंडली है कि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब संक्षिप्त कीजिए ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : जन-जीवन हरियाली अभियान चलाया और विश्व में सबसे बड़ी मानव श्रृखंला का निर्माण किया गया । साथ ही, जन-जीवन हरियाली के लिए 24 हजार

करोड़ की राशि भी प्रदान की गयी है । अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से, इस आसन के माध्यम से, एक युवा होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं माननीय वित्त मंत्री-सह-उप मुख्यमंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज मंजिल । आपका चार मिनट का समय है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, बजट का जो सत्य है उसे मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं । सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आयी है कि देश में आठ प्रतिशत बेरोजगारी दर है और बिहार के गांवों में साढ़े 13 प्रतिशत और शहरों में 18 प्रतिशत बेरोजगारी दर है । साढ़े चार करोड़ युवा बेरोजगार हैं, बिहार में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है ।

-क्रमशः-

टर्न-18/हेमन्त/03.03.2022

...क्रमशः..

श्री मनोज मंजिल : देश में आधी आबादी मात्र साढ़े चार हजार की कमाई पर गुजारा कर रही है । 84 प्रतिशत लोगों की आमदनी घट गयी और देश में 102 से 145 अरबपति हो गये । बिहार में चाहे विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, बैंक, कोई भी आप विभाग उठा लीजिए, 60 से 70 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहे हैं । बहुत शिक्षक की बहाली कर दिये । अरे, तीन साल में मात्र 37 हजार शिक्षकों की बहाली किये । साढ़े तीन लाख पद खाली पड़े हैं पूरे बिहार में । नौजवान, जवानी बर्बाद होती जा रही है नौजवानों की, ये सरकार जवानी खा रही है, नौजवानों के सपने मार रही है। उम्र बीत जा रही है । अरे, कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर गये थे आंदोलन करने। ये वही बच्चे हैं, मजदूर किसानों के, खून-पसीने के, खेत-खलिहानों के, गरीबों की संतान हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते, जो प्रोफेसर नहीं बन सकते, वकील, जज, डीएम, एसपी नहीं बन सकते, उन्हीं के बच्चे तो मास्टर बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अस्पतालों में नौकरी करना चाहते हैं स्टाफ में और सरकार बहाली नहीं कर रही है । केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में रिपोर्ट आयी 8,72,243 पद खाली पड़े हैं । जब बहाली नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, भर्ती नहीं, तो आरक्षण कहां से ? आरक्षण की हत्या हो रही है बिहार और पूरे देश में । इसके लिए हम मांग करते हैं इस सरकार से कि यह नहीं चलेगा कि बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन का, 2014 की बहाली

13,120 का अभी तक लटका कर रखे हैं । जो बच्चे फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिये थे, उनके बच्चे हो गये, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ताने सुन रहे हैं मां-बाप के, गांव-जवार के और इसीलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहाली कलेण्डर जारी करे और हिम्मत है सरकार को, तो रोजगार पर, नौकरी पर स्पेशल सत्र बुला ले दो दिन का, पास करा ले बिहार में और शिक्षा की क्या हालत है, नौवीं क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना जान रहे हैं 60 प्रतिशत से ज्यादा, अंग्रेजी की रीडिंग तक नहीं आती, मिडिल क्लास के बच्चों को जोड़, घटा, गुणा, भागा नहीं आता । अरे, कैसे उनका भविष्य बनेगा ? स्कूलों में शौचालय कहां हैं आपके ? गरीबों की बेटियां स्कूलों के पीछे जाती हैं, क्या उनकी लाज नहीं, क्या उनका सम्मान नहीं । उनका तो लाज-सम्मान है इस सरकार का कोई लाज सम्मान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में चले जाइये, पी0एम0सी0एच0 में, ओपीडी में 78 की संख्या के विरुद्ध मात्र 21 दवा हैं । आधी कमाई महंगाई में, आधी कमाई दवाई में, गरीब का खर्चा करी है बाल-बच्चा की पढ़ाई में । कितनी है कमाई और इसीलिए आज बिहार, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री मनोज मंजिल : 52 प्रतिशत लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं । महोदय, स्कूली बच्चे शिक्षा नहीं पूरी कर पाते ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मनोज मंजिल : शिक्षा का निजीकरण हो रहा है । गरीब के बच्चों को स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से बाहर करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय सदस्य ।

श्री मनोज मंजिल : इसलिए महोदय, एक मिनट । ये बिहार गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, कुपोषण से मुक्ति चाहता है ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री मनोज मंजिल : महंगाई से, जाति धर्म और नफरत की राजनीति से यह बिहार मुक्ति चाहता है ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अपने वित्तमंत्री जी तारकिशोर जी का..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये ।

श्री ललित नारायण मंडल : और श्रवण बाबू का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको यहां पर बोलने का मौका दिया है । अध्यक्ष जी, हमारे हर दिल अजीज वित्तमंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत बजट है वह काबिल-ए-तारीफ है । विरोध केवल विरोधी को करना है यह कोई नीति नहीं है, उसकी नीयति को देखना चाहिए । अध्यक्ष जी, विगत वर्षों में या तुरंत अभी जो कारोना काल गुजरा है उसमें हमारी सरकार ने क्या नहीं किया है। कोरोना को समुद्र के पास, समुद्र के पार भेजने में दिल्ली सरकार और बिहार सरकार ने सारी जुगत लगा दी और सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अभी तक 118800000 वैक्सीनेशन पूरा हुआ है । जिसके कारण कोरोना का प्रभाव बहुत कम हुआ है । दुर्भाग्य से यदि किसी परिवार में कोरोना के चलते मृत्यु हुई है, तो हमारी सरकार ने उस पीड़ित परिवार को प्रति मृत्यु पर 4 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया है और केंद्र सरकार से 50 हजार रुपये का अनुदान मिला है । यह साधारण बात नहीं है । यह बिहार है जहां पर यह 4 लाख रुपये का अनुदान मिला है और कहीं पर यह संभव नहीं है ।

अध्यक्ष जी, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

क्या नहीं हुआ है । हम भी आप ही की तरह गांव से आये हैं । सुना जाय । हम भी आप ही की तरह गांव से पढ़कर आये हैं । पहले गांव के स्कूल की क्या स्थिति थी,

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : उसको आप जानिये और अभी गांव के स्कूल की क्या स्थिति है, उसको आप समझिये ।

अध्यक्ष : आसन की ओर देखिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष जी, अभी शिक्षा की क्या स्थिति है उसको जानिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति ।

श्री ललित नारायण मंडल : अरे, हम प्रोफेसर हैं, गरीब के बेटे हैं । यह साधारण सी बात नहीं है । हमने पढ़ा है, हमने मेहनत की है

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री ललित नारायण मंडल : और तब हम प्रोफेसर बने हैं ।

अध्यक्ष : बीच-बीच में उठना उचित नहीं है ।

श्री ललित नारायण मंडल : कोई पैरवी हमको नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप आसन की ओर देखकर बोलिये । आप बैठे-बैठे मत बोलिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष जी, हमने कॉलेजों में देखा है कि जब से 15 साल से हमारी सरकार बनी है, क्या लड़के, क्या लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी है । उसको हमने अपनी नजर से देखा है और हमने बहुत सारी लड़कियों को अपने हाथ से, जो मैट्रिक पास की है उसको 25 हजार रुपया और जो इंटर पास की है उसको 50 हजार रुपया का चेक अपने हाथ से दिया है । यह बिहार में संभव है और दूसरी जगह संभव नहीं है ।

साथियो, पहले क्या होता था ? हमने जो देखा है उसकी बात हम करते हैं ।

अध्यक्ष : संदीप सौरभ जी, यह उचित नहीं है । आपके भाषण को भी सभी ने गौर से सुना है, इनका भी सुनिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : राज्य में जो सात निश्चय का कार्यक्रम चला..

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ललित मंडल जी नये सदस्य हैं और उस तरफ से जो माले के सदस्य हैं लग रहा है कि बैठे-बैठे आसमान में तीर छोड़ रहे हैं । आप लोग भी जब बोलियेगा और इधर के माननीय सदस्य अगर इसी तरह से बैठे-बैठे सवाल करेंगे, तो आप लोग भी नहीं बोल पायेंगे, तो नये माननीय सदस्य का ध्यान रखिये और जिस तरह से आप व्यवस्था बना रहे हैं यह सब लोग बैठे-बैठे देख रहे हैं । इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए महोदय । वह नये सदस्य हैं, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

टर्न-19/धिरेन्द्र/03.03.2022

अध्यक्ष : बैठ जाइये, यह बहस की जगह नहीं है । सदन की गरिमा के अनुकूल आप लोगों से अपेक्षा रहती है ...

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : तीर कहां से चलेगा, तीर तो आपके पास है, तीर कहां से छोड़ेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, चलिये ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हम देखते हैं कि गरीब विद्यार्थी जो पहले किसी तरह से कंपीटिशन की परीक्षा पास करते थे और इंजीनियरिंग में, मेडिकल में एडमिशन नहीं कराते थे, आज उसको सरकार लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है कि जा कर वहां एडमिशन

कराइये और लड़के एडमिशन कराते हैं । सरकार ने घोषणा किया है, अगर नौकरी लगेगी तो पैसा लौटा दीजियेगा, नहीं तो बिहार सरकार उस पैसा को पेड करेगी, तो यह गरीबों के लिए है ये सब पैसा ।

हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली तथा नाला का निर्माण कराया गया है । हर घर में भी, हमारा भी घर गांव में है, हम देखते हैं कि कराया गया, आपको नहीं दिखता है तो आप जानिये । हर घर बिजली की व्यवस्था की गई है । पहले याद कीजिये, उस जमाने को जब मोबाईल चार्ज करने के लिए सोचना पड़ता था, आप मोबाईल चार्ज करने के लिए सोचते थे कि किस दुकानदार का जी-हुजूरी करें कि हमारा मोबाईल चार्ज हो जाय । आज मोबाईल चार्ज करने की बात मत कीजिये, आज 24 घंटे में अधिकतम 23 घंटे तक बिजली रहती है, गांव में भी रहती है । हम गांव से आये हैं इसलिए विरोध की बात असत्य मत बोलिये ।

सात निश्चय-1 की सफलता से उत्साहित होने के बाद हमारी सरकार ने सात निश्चय-2 को सामने लाया है जिसमें पहली बात है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें 11,053 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसके तहत राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कानून बना है । विकसित बिहार की कल्पना इसी सरकार में हुई है, पहले क्या होता था, हमलोग जानते हैं ।

सशक्त महिला सक्षम महिला, इस योजना के तहत आज कार्य चालू है और हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । आप जाइये पंचायतों में, आप जाइये नगर निगमों में देखने के लिए, आधी आबादी महिला वहां पर अध्यक्ष के आसन पर आज विराजमान है और यह संभव अगर है तो इसी एन0डी0ए0 की सरकार के चलते । आधी आबादी आज शासन में है जिसको की आपलोग कोई वेल्यू नहीं देते थे ।

हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, इसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । लगभग सर्वेक्षण ही नहीं पूरा हुआ है, हम तो देखते हैं अपने गांव में कि जहां-जहां जिस-जिस खेत पर बोरिंग हो गया है, वहां पर बिजली भी पहुंचा दिया गया है और बोरिंग से पानी निकालकर हमारे गार्जियन खेती कर रहे हैं । इसलिए हर घर-घर की बिजली की बातें छोड़ दीजिये, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया गया है ।

स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी ग्रामीण वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का सर्वेक्षण पूरा हो गया है । इसके लिए 887 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है, हम इसके लिए पंचायती राज मंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हर गांव में जो स्ट्रीट लाईट लगाने की व्यवस्था किये हैं .....

उपाध्यक्ष : समय हो गया माननीय सदस्य ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, पहले क्या होता था, सारा अंधकार रहता था । आज तो गांव में लाईट की बात की जाती है, गांव की गलियों में आप जाइये और इसको लागू होने दीजिये, गांव की गलियां शहर की तरह चमकेगी, जब हर गली में स्ट्रीट लाईट लगेगी, सोलर स्ट्रीट लाईट लगेगी, तब आप इस बात को समझियेगा ।

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस पर 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसके तहत डोर-टू-डोर कचड़ा का उठाव होता है । हमारा घर सुल्तानगंज जैसे छोटे कस्बे में है, रोज सुबह दरवाजा खट-खटाकर आता है, व्हीसल बजाकर आता है ....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, व्हीसिल बजाकर आता है और कचड़ा उठा कर जाता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान जी । दो मिनट समय है आपका ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बजट पेश किया है, हम समझते हैं कि यह गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी बजट है । महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो चर्चा की कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है । आपने किया है, विद्यालय तो बनवाया है, भवन तो चमाचम है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है । मध्य विद्यालय के टीचर 10+2 में जाकर पढ़ाते हैं महोदय, ये सरकार का हालचाल है, ये सब लोग जानते हैं । महोदय, आज, 15 साल और 20 साल की बात मत कीजिये, किसान की चर्चा कर रहे थे, जहां हर खेत को पानी, हर खेत तक बिजली पहुंचा दिये हैं । महोदय, बिजली कनेक्शन पहुंचा दिये हैं लेकिन बिजली बिल का क्या हालचाल है, हमारी सरकार का इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है । बिजली बिल अनाप-सनाप आता है, हम एक बल्व जलाते हैं और जो एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसके बराबर एक बल्ब जलाने वाले लोगों को बिल आता है महोदय, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । आज रोजगार की बात करती है हमारी सरकार कि हमने रोजगार दिया, आज हमारे गांव के विभिन्न गांवों से, आज जाकर रेलवे स्टेशन पर आप देखिये जो हमारे मजदूर बोरे की तरह लद कर चाहे वह सहरसा हो, चाहे बेगूसराय हो, खगड़िया हो, हसनपुर हो, वहां से लद

कर दिल्ली, पंजाब दूसरे-दूसरे राज्य पलायन करते हैं महोदय और यह सरकार रोजगार की बात करती है । बजट में इसकी चर्चा कतई नहीं है । महोदय, आज कोरोना महामारी की बात हो रही है । महोदय, चर्चा कर रहे थे कोरोना महामारी में हमारे आशा कर्मी, हमारी आंगनबाड़ी सेविका, हमारे तमाम लोगों ने जान जोखिम में डालकर और हमारे पीड़ित को देखभाल करने का काम किया लेकिन आज जो उनकी पारिश्रमिक होनी चाहिए, सरकार कहती है कि हम न्यूनतम मजदूरी देंगे लेकिन आज हमारे आशा कर्मी को न्यूनतम मजदूरी 1,000 रुपया मिलती है । क्या 1,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी है ? महोदय, यह बजट में प्रावधान नहीं किया गया है कि हम आशा कर्मी....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये । माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, आंगनबाड़ी सेविका और मध्याह्न भोजन कर्मी जो विद्यालय में बच्चों को भोजन खिलाने का काम करती हैं वैसे लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान नहीं किया गया है । महोदय, मैं आसन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों को न्यूनतम मजदूरी देने की बात हो ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने नेता माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष की अनुमति से, मैं आज अपने राज्य के माननीय विकास पुरुष, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार के विकास के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । महोदय, सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2,37,691 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया, उसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं को लिया गया है । महोदय, हमारा राज्य शिक्षा की दृष्टि से बेहतर बने इसलिए सरकार द्वारा इस बजट में सबसे अधिक 39,191 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है ।

क्रमशः....

टर्न-20/संगीता/03.03.2022

...क्रमशः...

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, सरकार के प्रयास के कारण समाज के वंचित दलित वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है । वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच

अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन में 50.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

महोदय, हमने पिछले दो वर्षों में कोरोना त्रासदी को देखा है । बिहार सरकार द्वारा कोरोना संकट में भी स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर नहीं होने दिया । इसी को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा राशि दी गई है । यह राशि 16 हजार 134 करोड़ है ।

सरकार राज्य में शहरों के साथ-साथ गांवों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसका सरकार ने पूरा ध्यान रखा है । सरकार ने सभी 38 जिलों में शिशु केयर यूनिट तथा 30 जिला अस्पतालों में 10-10 बेड का आई0सी0यू0 का निर्माण 122 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए बजट में राशि खर्च करने का प्रावधान किया है ।

महोदय, समाज के समग्र विकास के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण आवश्यक है । बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर ने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की है । महात्मा गांधी भी कहते थे 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' । इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2007 में ही एक अलग विभाग का गठन किया और इस समाज के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना मुसहर एवं भुईयां समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय योजना चलायी, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना और विकास मित्रों की बहाली हमारे मुख्यमंत्री जी के दलितों के उत्थान के सोच का नतीजा है । अभी राज्य में 9000 विकास मित्र कार्यरत हैं ।

महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास निगम का गठन सरकार द्वारा किया गया है । महोदय, अगर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की बात करूंगी तो समय कम पड़ जाएगा । विकास की इतनी लंबी लाइन है जो सुनाते-सुनाते भी थक जाएंगे ।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया ऐसा बजट है जो न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य बल्कि आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा । कोरोना संकट के बाद भी वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए जिस तरह का बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है उसके लिए हमारे माननीय विकास पुरूष मुख्यमंत्री महोदय तथा उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों ही बधाई के पात्र हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : थोड़ा सा बचा हुआ है सर, इसको शामिल कर लीजिए ।

उपाध्यक्ष : भिजवा दीजिए ।

श्री रामविलास कामत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के सामान्य बजट के विमर्श में आपने हमें समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मैं इस सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके सौजन्य से आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं । मैं इस सदन के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श के लिए मुझे मौका मिला है । अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किए हैं, यह बजट बिहार के विकास के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने वाला है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बजट पेश की गई है, जिसका आकार 2.37 लाख करोड़ है आज यूं ही इतने आकार की बजट नहीं हो गई है । 2005-06 से अगर हम देखेंगे तो साल दर साल बढ़ते बढ़तें यह बजट यहां तक पहुंची है । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सरकार के द्वारा अभी पेश की गई है, इस बजट में सबसे अधिक प्रावधान शिक्षा विभाग के मद में किया गया है । शिक्षा विभाग में 39 हजार 191 करोड़ का प्रावधान किया गया है फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए 16 हजार 134 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है, उद्योग पर 1643 करोड़ और कृषि पर 7 हजार 712 करोड़ का प्रावधान इस बजट में की गई है, कल्याण पर खर्च करने के लिए 12 हजार 375 करोड़ इस बजट में प्रावधान किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रावधान के अनुसार जो गांव के विकास की बात है इन्फ्रास्ट्रक्चर की, विकास की बात है उसके लिए भी 1550 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आंकड़ा है, जो बजट पेश किया गया है उसका जो आंकड़ा है, उसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया है । बजट में शिक्षा पर कुल 39 हजार 191 करोड़ रुपया रखा गया है जो बजट का 16.5 प्रतिशत है । शिक्षा के कुल बजट में वर्ष 2022-23 में स्कीम मद में 22 हजार 198 करोड़ रुपया तथा स्थापना तथा प्रतिबद्ध मद में 16 हजार 953 करोड़ रुपये खर्च होंगे । बजट के प्रावधान के मुताबिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30 हजार 620 पदों पर छठे चरण में नियोजन की कार्रवाई भी

की जाने की प्रक्रिया की गई है इस बजट में । उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की कुल 40 हजार 558 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसका प्रावधान इस बजट में किया गया है । सभी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर सृजित 8 हजार 386 पद बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो योजना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों के भवन की आवश्यकता 15 हजार 941 के विरूद्ध 15 हजार 653 विद्यालय भवन का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है, बाकी बचे भवनों का कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा जो इस बजट में प्रावधान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 402 करोड़ रुपये खर्च किए थे जो आगे भी जारी रहने का इस बजट में प्रावधान किया गया है । बच्चों के पोशाक को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 898 करोड़ रुपये की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता में भेजा गया था जो आने वाले वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगा, चालू रहेगा और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा ।

कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा विद्यालय संचालित की जा रही है, जिसमें 50 हजार 963 बालिकाएं पढ़ाई कर रही हैं जिनकी हर सुविधा को जारी रखने का बजट में भी प्रावधान किया गया है ।

..क्रमश:...

टर्न-21/सुरज/03.03.22

...क्रमश:...

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों में उत्क्रमित एवं नव सृजित प्लस टू स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 7 हजार 530 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य, उसके क्षेत्र में भी कई काम करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में जो खर्च करने का प्रावधान हुआ है वह है 16 हजार 134 करोड़ रुपये का । राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य विभाग के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के

सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ पांच-पांच स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कुल 1 हजार 379 स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर कार्य चल रहा है, जो इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है । कुल 1 हजार 754 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति इन सारे कार्यों को पूरा करने में बजट में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पी0एम0सी0एच0 मेडिकल कॉलेज को 5 हजार 462 बेड क्षमता का आधुनिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है । हम सभी जानते हैं कि यह पटना का पी0एम0सी0एच0 पूरे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिये जो सरकार प्रयास कर रही है इसके लिये मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आई0जी0आई0एम0एस0 अस्पताल में सौ बेड का स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना तथा 1 हजार 2 सौ अतिरिक्त बेड के अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है । महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किये जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में सौ बेड के कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जो उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है । इसके लिए भी मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, इस बजट में उद्योग पर भी बहुत सारे काम करने के लिए प्रावधान किया गया है । उद्योग के बजट में निवेश पर 1 हजार 643 करोड़ रुपया खर्च कर राज्य में कई उद्योगों की स्थापना एवं उद्यमों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है ।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में 7 हजार 712 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । वर्ष 2007 से राज्य में कृषि रोडमैप के तहत कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं । इस बार भी मुर्गी पालन, मछली पालन, गोवंश एवं सहकारिता के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है । कृषि को उद्योग से जोड़कर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है ।

महोदय, गांव के विकास के लिए गांव में जो 80 प्रतिशत लोग रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए, सड़क के निर्माण के लिए, उनकी हर एक सुविधाओं को

चुस्त और दुरूस्त करने के लिए इस बजट में 29 हजार 749 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे । राज्य की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है इसके लिए गांवों में रहने वाली आबादी के लिए सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं को बहाल रखने तथा बढ़ाने के लिए बजट में ध्यान रखा गया है । शहरों के लोगों के लिए भी बजट में अनेक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जो शहर को बेहतर और सुंदर बनाने के काम आएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल्याण के क्षेत्र में जो इस बजट में महत्वपूर्ण आंकड़ा इसमें दिया गया है राज्य में एस0सी0, एस0टी0, पिछड़ा, अति पिछड़ वर्ग, महिला और बच्चों के अलावा दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन योजनाओं के लिए 12 हजार 375 करोड़ खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है । इन वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लागू रखने एवं नई योजना चालू करने पर यह राशि अगले वित्तीय वर्ष में खर्च किये जाएंगे ताकि इन वर्गो के लोगों को और विकास करने का मौका मिल सके, आगे बढ़ने का मौका मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने जिन बातों की चर्चा आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष किया है हम समझते हैं कि इसके अलावे इस बजट में बिहार सरकार की जो अन्य निश्चय है उस निश्चय पर जब चर्चा करेंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह बजट बिहार को विकसित बिहार, सुंदर बिहार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बजट है और इस पर काम किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के जो सात निश्चय के पार्ट-1 हैं उसके तहत जो काम किये गये हैं, वह सराहणीय रहा है और उसमें हम सभी जानते हैं और कह सकते हैं कि बिहार में जो सात निश्चय-1 का कार्यक्रम चला उसमें युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो काम किया गया वह बहुत ही बेहतरीन रहा है और छात्रों को, युवाओं को आगे बढ़ने में वह काफी मददगार रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सात निश्चय पार्ट-1 में जो हर घर बिजली पहुंचाने की बात की गई वह कार्यक्रम भी ऐसे ही नहीं हो गया उसके लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी जो पटना के गांधी मैदान से संकल्प ले करके कहे थे कि हम वर्ष 2015 तक हर घर तक बिजली पहुंचायेंगे, तभी हम वोट मांगने के लिए जाएंगे । तो इस संकल्प को पूरा करके सरकार ने दिखाया है और आज बिजली के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से

खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम जो चालू किया जा रहा है जिस पर काम शुरू हो गया है वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । किसान...

उपाध्यक्ष : समय हो गया आपका ।

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए यह खेतों तक पानी पहुंचाने का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचाने का इसके लिए मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ताकि किसानों का इसका बहुत ही अधिक लाभ मिल सके, वह आगे बढ़ सकें, उनकी तरक्की हो सके, उनका...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये । माननीय सदस्या श्रीमती स्वर्णा सिंह जी ।

श्री रामविलास कामत : बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बिहार विधान मंडल के इस सत्र में माननीय वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर अपनी पार्टी कि ओर से अपने विचार को आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया गया है । महोदय, लगातार दो वित्तीय वर्ष कोरोना महामारी की चपेट में रहे देश कि आर्थिक स्थिति भी खराब हुई, बिहार का भी विकास दर गिरा । अनुमान 10.38 प्रतिशत का था पर 2020-21 में विकास दर 2.5 प्रतिशत रहा । बिहार में पॉजीटिव ग्रोथ रेट बना रहा । बजट के अनुसार बुरा दौरा पार हो गया है और अब विकास का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ेगा । सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने के लिए 16 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये का प्रावधान किया गया है । सरकार ने लोगों के जीवन को छुने वाले एवं बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने वाले सात निश्चय-2 के लिए 5000 करोड़ के बजट का प्रावधान कर अपना संकल्प दोहराया है ।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक एवं आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए काम की जाएगी ।

...क्रमश:...

टर्न-22/राहुल/03.03.2022

श्रीमती स्वर्णा सिंह : ..क्रमश:... कुल बजट का 16.5 प्रतिशत खर्च शिक्षा पर किया जाएगा । महोदय, सरकार राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है । मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अन्तर्गत वंचित वर्ग को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी गई है । इस वित्तीय वर्ष में उद्योग एवं उद्योग निवेश मद में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है । आने वाले वर्षों में इसका असर रोजगार बढ़ाने में दिखेगा । महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं । किसानों की आय में वृद्धि करने पर भी सरकार का फोकस है । सरकार द्वारा 54 बाजार प्रांगण को विकसित करने के लिए 2046 करोड़ रुपये खर्च करेगी । दलहन और तिलहन की उपज को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को दलहन और तिलहन के बीज भी फ्री में उपलब्ध करायेगी ।

महोदय, बिहार की आत्मा गांवों में बसती है और 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है । इसके लिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीणों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है जिसके लिए सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है । सभी गांवों में सरकार द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट लगायी जायेगी । सरकार ने इसके लिए भी समुचित धन उपलब्ध कराया है । महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए तन-मन-धन से कार्य कर रही है । साथ ही दिव्यांगजनों वृद्धजनों एवं वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी ने इनका भी पूरा ख्याल रखा है । महोदय, वर्ष 2020 से महामारी एवं आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार अपने विवेक से राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा राज्य में वित्तीय असंतुलन नहीं होने दिया । इस विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर जनता के लिए अनेकों जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत एवं सतत रखने का प्रयास किया गया है । अब हम सभी को इस आवंटित राशि का पूर्ण सदुपयोग हो इसके लिए सतत् प्रयास करना है। पुनः मैं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 सत्येंद्र यादव जी ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2022 का अनुपूरक प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में मुझे 2-3 बातें महत्वपूर्ण रूप से कहनी हैं । हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में बिहार के युवाओं के लिए एन0डी0ए0 की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । अच्छे काम का नमूना है कि उद्योग विभाग को पूरे बजट में 1643 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 1643 करोड़ रुपये

में 6 पार्क में 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे । मुझे यह बात कहनी है कि बिहार की 12-13 करोड़ की आबादी में 1643 करोड़ रुपये में ये कौनसी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे । बिहार मानव श्रम प्रधान राज्य है और बिहार के डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार को उद्योग को प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए लेकिन सरकार के लोग जितने भी भाषण कर रहे हैं उद्योग सरकार की निगाहों में, प्राथमिकता में नहीं है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उद्योगों को प्राथमिकता में लेना चाहिए और 1643 करोड़ का जो बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है बड़े लोग ताली ठोक कर कह रहे हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि बिहार के अंदर 24 घंटा बिजली देते हैं तो सोलर लाईट प्लेट की गांवों के अंदर क्या जरूरत है । यह सोलर लाईट प्लेट के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उस पैसे को उद्योग पर आप अटैच कर देते, उस पैसे को उद्योग पर लगाते तो हमाने बिहार के अंदर उद्योग होता । यह सोलर लाईट प्लेट की स्कीम जो है वह पंचायतों को आपने दे दी लेकिन पंचायतों को निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया । वह निर्णय होगा बियाडा और कौन लगाएगी यह सब लोग कुछ दिनों के बाद जानेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो बजट है वह काँट्राडिक्टिक बजट है । यह तय होना चाहिए कि बिहार जो शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से आज छटपटा रहा है । सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है शिक्षा में बजट की बढ़ात्तरी की है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन जितनी जरूरत हो बजट का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए । युवाओं को रोजगार के सवाल पर बजट की खामोशी ने बिहार के नौजवानों में नाउम्मीद पैदा की है । आपको पीठ जितनी थपथपानी है थपथपा लो लेकिन आपका बजट पढ़कर बिहार का एक भी नौजवान आपके पक्ष में कोई पॉजीटिव प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप सब विधायक यहां बैठे हुए हैं ये चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण कार्य विभाग की । सब विधायकों के बोर्ड लगते हैं, प्लेट लगते हैं रोडों पर । ग्रामीण कार्य विभाग अगर नहीं हो तो विधायक का नामोनिशान मिट जाएगा गांवों के अंदर सड़कों पर । 1 लाख 25 किलोमीटर सड़कें मेंटिनेंश के लिए हैं, 60 हजार किलोमीटर सड़कें पंचवर्षीय प्लान से पार कर चुकी हैं । माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं विचार करने की जरूरत है । 2 हजार करोड़ रुपया मेंटिनेंस का ऐम इन लोगों ने दिया है और 2 हजार करोड़ रुपया में जो 60 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता । आप विकास की बात कर रहे हैं ग्रामीण कार्य विभाग पास पैसे नहीं होंगे तो गांव की सड़कें नहीं बनेंगी और

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट असंतुलित है, यह बजट अपने-आप में अंतर्विरोधी है और इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है । जहां तक कृषि की चर्चा चल रही है । बिहार सरकार कृषि के डेवलपमेंट के लिए जोर-जोर से ताली पीट रही है, बिहार के किसानों की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, चले जाइये गंगा के उस पार जिले के एक-तिहाई हिस्से में जल-जमाव की समस्या है । जल-जमाव का निस्तारण करने के लिए योजना होनी चाहिए, वह योजना नहीं है । हम कई वर्षों से लगे हैं, हमसे पहले के विधायक भी और उनसे पहले के भी विधायक छटपटाते रहे जब सारण जिले के अंदर सारण प्रमंडल के अंदर जो जल-जमाव की समस्या है उसके निदान के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए लेकिन बजट के संतुलित खर्च के चलते गंगा के उस पार के इलाकों को हम जल-जमाव से मुक्ति नहीं दिला सके । उसको जल-जमाव से मुक्ति देते, उस पर बजट खर्च करते तो खेती में उन्नति आती, खेती में पैदावार बढ़ती लेकिन आपकी प्राथमिकता में वह नही है और जिसके चलते कृषि डेवलप नहीं हो रही है । आप कह रहे हैं कृषि विकास और किसानों के लिए बहुत-सी योजनाएं चल रही हैं दलाल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दलाल लूट रहे हैं किसानों को फायदा नहीं हो रहा है । कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भूमि सुधार के साथ जल-जमाव की समस्या का निदान होना चाहिए और हर...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

हर किसान के खेत तक पानी के लिए जल संसाधन विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं वे कागज पर हैं, उस पैसे का भ्रष्टाचार में इस्तेमाल होता है । बिहार को विकसित बिहार बनाना है तो कृषि, रोजगार और शिक्षा पर आपको फोकस करना चाहिए । आपने कहा सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा पैसा खर्च किया है । आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आप पैसा खर्च करते हैं, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो पैसा आप देते हैं वह क्या वास्तव में बच्चों को मिलता है । वह पैसा आपके अधिकारी गटक जाते हैं आप सामाजिक क्षेत्रों में और चर्चा करते हैं स्किल डेवलपमेंट करिये, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पैसे जाते हैं इसलिए...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का जो बजट है वह असंतुलित है और इस बजट से बिहार का विकास नहीं होगा । बेईमान, भ्रष्ट लोगों और ठेकेदारों के हाथ में इस बजट की बड़ी राशि जाएगी इसलिए सरकार को पुन: विचार करना चाहिए और उद्योग विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में भी बढ़ोत्तरी करके सड़कों का निर्माण कराना चाहिए और स्ट्रीट

लाईट, मैं सख्त एतराज जताना चाहता हूं आपने स्ट्रीट लाईट का प्रोग्राम दिया है और आप कहते हैं कि आप 24 घंटे बिजली देते हैं तो...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये । माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार साहनी जी ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : अपनी बात पर कायम रहिये । जब 24 घंटे बिजली देते हैं तो स्ट्रीट लाईट की कोई जरूरत नहीं है यह अगर आपने शुरू किया है तो बड़ी कंपनियों को ठेका देने के लिए किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट को संतुलित कीजिये और जो बजट इधर-उधर खर्च कर रहे हैं उस बजट को जोड़कर उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाइये जिससे...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल सके । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो लाया गया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो रखा गया है वह बजट सरासर गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अतिपिछड़ा विरोधी है, मछुआ विरोधी है यह बजट । मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यह जो गीत गा रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-23/मुकुल/03.03.2022

...क्रमशः...

श्री अनिल कुमार साहनी : माननीय वित्त मंत्री जी ये गीत पुराना गाते हैं, बिहार के गरीबों और नौजवानों को भरमाते हैं और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं । जिस प्रकार से इस बजट को लाया गया है, इसमें बताया गया है कि कृषि पर 29 हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो आप 29 हजार करोड़ रुपया कहां खर्च करेंगे । कृषि के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अगर 29 हजार करोड़ रुपये में से किसानों के पास 5 परसेंट भी पैसा नहीं पहुंचता है, आपके कमीशन में वह पैसा चला जाता है । आप कहते हैं कि 29 हजार करोड़ रुपये देंगे, किसान और मजदूर आज किस प्रकार से इस कोरोनाकाल में और आये हुए बाढ़ में किस प्रकार से किसान और मजदूरों का हाल रहा, आपने अभी तक कृषि इनपुट का पैसा नहीं दिया । आपने कहा कि कृषि इनपुट के द्वारा हम किसान को पैसा देंगे, आज तक हमारे कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी किसान को सही रूप से नहीं मिला है और आप कहते हैं कि कृषि के लिए नया बजट लाये हैं, वही गीत पुराना गाते हैं और आपने कहा कि शिक्षा पर 39 हजार करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो आप 39 हजार करोड़ रुपया कहां पर खर्चा करने जा रहे हैं । अभी तक हमारे ही क्षेत्र में कई जगह देखिए बड़े-बड़े

बिल्डिंग बन गये, मगर बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, क्या आप उसपर खर्चा करने जा रहे हैं या इसमें भी बंदरबांट करने जा रहे  हैं । यह बजट जो दिखाई दे रहा है, बिहार की जनता को सरासर धोखा देने वाला बजट दिखाई पड़ रहा है और इसके माध्यम से सिर्फ लूट किया जायेगा । आपने जल-नल, मैं तो कहता हूं जल-नल छल है, बहुत बड़ा छल है । माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर गये थे, मैंने समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी संयोग से आप आज हेलीकॉप्टर से नहीं आये हैं, आप बाई कार से आये हैं और कार से आप जाइयेगा तो हमारे ही विधान सभा क्षेत्र से जिसमें 8-9 पंचायत पड़ेगा, रामदयालु से लेकर फकुली तक । माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी भी पंचायत में जाकर देख लीजिए कि जल-नल का क्या हाल है । बजट आप दे रहे हैं तो जल-नल का मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस करने के लिए आप पैसा  दीजिए । हमलोग जो विधायक हैं जहां भी जाते हैं, यहां पर हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष के भी विधायक बैठे हुए हैं, आपलोग भी दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपकी जनता कहती है कि नहीं कि जल-नल फेल हो गया है, हमें चापाकल चाहिए, बोलता है कि नहीं कि हमें चापाकल चाहिए तो आप जल-नल के नाम पर बिहार को छलने का काम किये हैं, आप छलिया हैं, आप इस बिहार की गरीब जनता को, शोषित/उपेक्षितों को जिस प्रकार से आपने ठगने का काम किया है यह जनता माफ करने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर हम 16 हजार करोड़ रुपया देंगे, कहीं पर दवाई नहीं, कहीं पर खटाई नहीं और कहीं पर बेड नहीं । हमारा जो पारस हॉस्पिटल में लूट हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है । अगर कोई व्यक्ति संयोग से अपनी जान बचाने के लिए उसमें चला गया तो 10-20 लाख रुपया दे देता है उसके बाद जब कहा जाता है कि अब पेसेंट को दूसरी जगह ले जाइये तो मरीज के परिजन विधायकों के पास, आपलोगों के पास भी जाते होंगे और कहते होंगे कि यहां से पी0एम0सी0एच0 में भिजवा दीजिए, इंदिरा गांधी में भिजवा दीजिए या एम्स में भिजवा दीजिए, पैसा जब खत्म हो जाता है, जब पारस में वह पैसा से लूटा जाता है तो इसको भी देखने वाला कोई नहीं है । इस बजट में जांच भी करने की प्रक्रिया रखिए कि आपका कितना-कितना पैसा लूटा जा रहा है । वहीं पर आपने जो मत्स्य और पशु पालन, आज मछुआरा समाज के लाखों, निषाद समाज के, मल्लाह समाज के जिनका जलकर से जीवन चलता है और उनको कहीं-कहीं, जल-जीवन-हरियाली में उनको जो है, मिट्टी भरा जा रहा है । आज लाखों मछुआरे, लाखों मल्लाह/निषाद के लोग, जिनका परम्परागत मछली पालन करने का और मछली पर आधारित रहने का जो काम था, आज उसपर रोक

लगता जा रहा है, आप उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किये हैं कि इनका जो रोजी-रोटी परम्परा है वह कहां जा रहा है । वहीं पासी भाइयों के लिए आपने किसी प्रकार का इसमें प्रावधान नहीं किया, जो परम्परागत पासी भाई थे जो पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतारते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नीरा का उत्पादन कीजिए तो नीरा का उत्पादन करने के लिए आपने कोई बजट नहीं दिया । आप उन पासी समाज के लोगों से ताड़ी को खरीद लीजिए और उसका नीरा बनाइये और मार्केट में बेचिए । आज पासी समाज जो 20 फीट/50 फीट ऊपर जाकर ताड़ उतारता है और नीचे में जो मल्लाह मछली निकालता है, आज मल्लाह और पासी का जो समीकरण था इस कारण से खत्म होता जा रहा है और वे पकड़ा-पकड़ा कर जेल में जा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री जी आपने प्रावधान नहीं किया कि पासी समाजों का, आप जो नीरा बनाइयेगा उसके लिए फैक्ट्री कहां-कहां खोल रहे हैं, उसमें आप नीरा बनाने के लिए कितना करोड़ रुपया दे रहे हैं, नीरा बनाने वाले लोगों के लिए, पासी समाज के लिए, नीरा उद्योग खोलने के लिए, जो परम्परागत काम करते थे पेड़ पर से वह उतारे और आप उसी जगह उनसे खरीद लीजिए, आप उनसे खरीद लीजिए । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप इन गरीब और गुरबों को जो सताने का काम कर रहे हैं, आप उनके पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं तो यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है । जो बजट प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022-23 पर 2 लाख 37 हजार 691 रुपया का जो आपने पेश किया है, यह लगता है कि सिर्फ बंदरबांट करने के लिए पेश किया गया है और इससे किसी आने वाले बिहार के लोगों को, जैसे आप इस 15 सालों से जो बजट पास कर रहे हैं, कहीं पर आपका दिखाई नहीं पड़ता है, किसी भी गरीब के घर में, झोपड़ी वाले के घर में, इस बजट के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, यह हमलोग अपने क्षेत्र में ही देखते हैं ।

(व्यवधान)

सुनिये, अब सही बात बोलेंगे तो लगेगा ही । 'सत्य कहे सो मारा जाय और झूठा जग पतिआये' और बिहार के लोग होशियार हो गये हैं आपके इस बहकाने वाले कार्य में पड़ने वाले नहीं हैं और आप इस बजट के माध्यम से जिस प्रकार से ठगने का काम कर रहे हैं, वे ठगाने वाले नहीं हैं । झूठ बोलकर और झूठ का काम करके आप गरीबों को बहकाने वाले नहीं हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह प्रावधान करवाइये कि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : आपलोगों को बोलना चाहिए ।

''सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं ।''

आपमें सत्य कहने का हिम्मत नहीं है, सत्य सुनने का भी हिम्मत नहीं है, आप सत्य की ओर जाने वाले नहीं हैं । आप जिस प्रकार से इस बजट को बनाये हैं वह गरीब विरोधी है, मजलूम विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और बेरोजगारी से जो मर रहा है ।

अध्यक्ष : क्या इनका समय और बढ़ा दिया जाय ?

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, नहीं ।

अध्यक्ष : आप लोग बताइये कि क्या इनका समय बढ़ा दें ।

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, 19 लाख रोजगार पर कुछ नहीं बोले, उसमें कितना बजट दे रहे हैं, 19 लाख बेरोजगार लोग जो मर रहे हैं । आज जब वे सड़कों पर, राज्यपाल जी के यहां, मुख्यमंत्री जी के यहां धरना देने जाते हैं तो लाठी से पीटकर भगाया जाता है, सरकार को उसपर भी कुछ बजट रखना चाहिए था कि गरीब/नौजवान जो रोड पर भुखमरी का शिकार हो गये हैं । मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको सुझाव देता हूं कि गरीब/नौजवान/बेरोजगारों के प्रति भी आप इस पर विचार कीजिए और उनको 19 लाख नौकरी दीजिए ।

अध्यक्ष : बजट पर सामान्य विमर्श कल भी जारी रहेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 03 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-40 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।